

①

छत्तीसगढ़ शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0) 492002

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक/03/2019

क्रमांक/520/21-ब/छ0ग0/19, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा वेतन पुनरीक्षण, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नियम, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

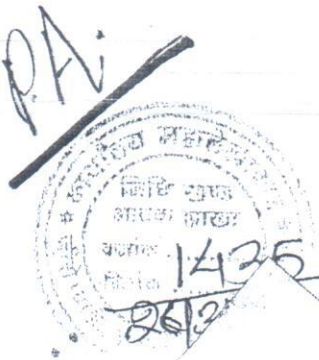
1. नियम 11-क(2) में, खण्ड (1) एवं (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(1) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को देय पेंशन उसकी सेवानिवृत्ति के समय धारित-पद के पुनरीक्षित वेतनमान में न्यूनतम वेतन का 50 प्रतिशत होगा, जो अनुसूची 2(दो) और 3(तीन) के अनुसार होगा :

परन्तु यह कि पेंशन के पुनरीक्षण एवं पुनर्निर्धारण के समय विद्यमान पेंशन का निम्नानुसार पहले समेकन किया जायेगा-

- | | |
|-------|---|
| (एक) | दिनांक 1-1-2006 के विद्यमान पेंशन |
| (दो) | दिनांक 1-1-2006 को मंहगाई पेंशन |
| (तीन) | दिनांक 1-1-2006 को विद्यमान मूल पेंशन और मंहगाई पेंशन विद्यमान दर से मंहगाई राहत: |

परन्तु यह और कि वे सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 01 नवम्बर, 2000 के पश्चात् तथा 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने के कारण सेवा में नहीं रहे हैं और उनकी वह पेंशन, जो



उक्त नियम के अनुसार पुनरीक्षित की गई है, दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 03.07 गुना बढ़ाकर पुनरीक्षित की जाएगी जो उनकी सेवानिवृत्ति के समय अंतिम आहरित वेतन के समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी ।

- (2) पुनरीक्षित पेंशन, खण्ड (1) में उल्लिखित अनुसार पुनरीक्षण वेतन का न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा उपरोक्तानुसार निर्धारित समेकित पेंशन, जो भी अधिक हो, होगा:

परन्तु यह कि ऐसे न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 01 नवम्बर, 2000 के पश्चात् तथा दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त हो गए थे और जिनकी पेंशन, उक्त नियम के अनुसार पुनरीक्षित की गई है, के संबंध में पारिवारिक पेंशनरों के मामले में पूर्ण परिवार पेंशन को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 03.07 गुना बढ़ाकर पुनरीक्षित किया जाएगा जो संबंधित न्यायिक अधिकारी के सेवानिवृत्ति के समय अंतिम आहरित वेतन के समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी।”

NOTIFICATION

No...../520/XXI-B/C.G./19, In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Judicial Service Pay Revision, Pension and Other Retirement Benefits Rules, 2003, namely:-

AMENEMENT

In the said rules,-

1. In rule 11-A(2), for clause (1) and (2), the following shall substituted, namely:-

"(1) The revised pension of the retired Judicial Officer should be 50% of the minimum pay of the revised pay scale of the post held by

him at the time of the retirement, which shall be as Schedule 2 and 3:

Provided that at the time of revision and re-fixation, the existing pension shall be consolidated first as follows:-

(i)	Existing pension as on 1-1-2006
(ii)	Dearness pension as on 1-1-2006
(iii)	Dearness relief at prevalent rate on both the existing basic pension and Dearness pension as on 1-1-2006

Provided further that the Judicial Officers, who have ceased to be in service due to death or retirement after 1st November, 2000 and prior to 1st January, 2006, their pension, which has been revised in accordance with the said rules, shall be revised by raising the same by 03.07 times w.e.f. 1st January, 2006 which shall not be less than 50% of the revised pay of revised pay scale equivalent to the last pay drawn at the time of his retirement.

- (2) The revised pension shall be fixed at minimum 50% of the revised pay as mentioned in para (1) or consolidated pension as calculated above, whichever is higher:

Provided that such Judicial Officer who retired after 1st November, 2000 and prior to 1st January, 2006 and whose pension has been revised in accordance with the said rules,

उक्त नियम के अनुसार पुनरीक्षित की गई है, दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 03.07 गुना बढ़ाकर पुनरीक्षित की जाएगी जो उनकी सेवानिवृत्ति के समय अंतिम आहरित वेतन के समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी ।

- (2) पुनरीक्षित पेंशन, खण्ड (1) में उल्लिखित अनुसार पुनरीक्षण वेतन का न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा उपरोक्तानुसार निर्धारित समेकित पेंशन, जो भी अधिक हो, होगा:

परन्तु यह कि ऐसे न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 01 नवम्बर, 2000 के पश्चात् तथा दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त हो गए थे और जिनकी पेंशन, उक्त नियम के अनुसार पुनरीक्षित की गई है, के संबंध में पारिवारिक पेंशनरों के मामले में पूर्ण परिवार पेंशन को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 03.07 गुना बढ़ाकर पुनरीक्षित किया जाएगा जो संबंधित न्यायिक अधिकारी के सेवानिवृत्ति के समय अंतिम आहरित वेतन के समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी।”

NOTIFICATION

No...../520/XXI-B/C.G./19, In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Judicial Service Pay Revision, Pension and Other Retirement Benefits Rules, 2003, namely:-

AMENEMENT

In the said rules,-

1. In rule 11-A(2), for clause (1) and (2), the following shall substituted, namely:-

"(1) The revised pension of the retired Judicial Officer should be 50% of the minimum pay of the revised pay scale of the post held by

the full family pension in respect of the family pensioners shall be revised by raising the same by 03.07 times w.e.f. 1st January, 2006 which shall not be less than 30% of the pay of revised pay scale equivalent to the last pay drawn by the Judicial Officer at the time of retirement."

**By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,**

sd/
(Ravishankar Sharma)

Principal Secretary

Government of Chhattisgarh,

Law & Legislative Affairs Department

पृ.कमांक 2883/520/21-ब/छ.ग./2019

रायपुर, दिनांक 08/03/2019
08 MAR 2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, छ.ग. उच्च न्यायालय, बोदरी, बिलासपुर,
2. महालेखाकार, जीरो पॉइन्ट, रायपुर,
3. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर,
4. सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर,
5. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर
6. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग.शासन, महानदी भवन, मंत्रालय अटल नगर, रायपुर की ओर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन के अवलोकनार्थ
7. मान. विधि मंत्री जी के निज सचिव की ओर मान. विधि मंत्री जी के अवलोकनार्थ,
8. श्री अम्बरीश कुमार पटेल, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नवोदय स्कूल गेट एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पास, एन.एच. 69, ग्राम ब्यावरा, पोस्ट पावरखेड़ा फॉर्म, तहसील व जिला होशंगाबाद (म0प्र0),
9. अवर सचिव (स्थापना/लेखा), विधि और विधायी कार्य विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर,
10. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
11. उप संचालक, शासकीय मुद्रणालय, इंद्रावती भवन के सामने, अटल नगर, रायपुर की ओर राजपत्र असाधारण के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।
12. श्री के.एल.बागडे, अवर सचिव (नोडल ऑफिसर) विभागीय वेबसाईट की ओर विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

MK
68.3.19
(मनीष कुमार ठाकुर)

अतिरिक्त सचिव

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय

F.No.45/08/2017-FF(P)

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
Freedom Fighters & Rehabilitation Division

2nd Floor, NDCC-II Building,

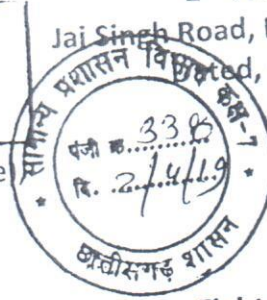
Jai Singh Road, New Delhi - 110 001,
Dated, the 26th March 2019.

29 MAR 2019

To

Chief Controller of Accounts (Home)

O/O CHIEF SECRETARY
Govt of Chhattisgarh
DAK-CS-3938
Date 30-03-2019



The Pr. Chief Controller of Accounts (Home)
Ministry of Home Affairs,
MDCNS, New Delhi-110 001

Subject: Grant of Dearness Relief to Central Freedom Fighter Pensioners w.e.f. 01.01.2019 -regarding

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter No.45/08/2017-FF(P) dated 03.10.2018(copy enclosed) regarding 7% Dearness Relief to be paid to the freedom fighter pensioners w.e.f. 01.07.2018 and to say that recently Dearness Relief in respect of Central Government pensioners has been enhanced by 3% by the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Pension & Pensioners' Welfare, New Delhi's O.M. No.42/04/2019-P&PW(D) dated 06.03.2019. Hence the Dearness Relief admissible to the Central Freedom Fighters/spouse/daughter pensioners shall be enhanced from the existing rate of 7% to 10% w.e.f. 01.01.2019. All the banks are requested to calculate the arrears w.e.f. 01.01.2019. The payment of arrears of Dearness Relief shall not be made before the date of disbursement of pension/family pension of March, 2019. The revised amount of pension for various categories of pensioners after increase of 3% DR i.e. total 10% Dearness Relief will be as follows:

Sl No.	Category of freedom fighters	Basic amount of pension (per month)	Enhanced amount of pension after adding 10% DR (per month) w.e.f. 01.01.2019
1.	Ex-Andaman Political prisoners/spouses	Rs.30,000/-	Rs.33,000/-
2.	Freedom fighters who suffered outside British India/spouses	Rs.28,000/-	Rs.30,800/-
3.	Other Freedom fighters/spouses including INA	Rs.26,000/-	Rs.28,600/-
4.	Dependent parents/eligible daughters (maximum 3 daughters at any point of time)	50% of the sum that would have been admissible to the freedom fighters, i.e. in the range of Rs.13,000/- to Rs.15,000/-	50% of the sum that would have been admissible to the freedom fighters, i.e. in the range of Rs.14,300/- to Rs.16,500/-

....p.

705
24-19

imp
ASCM(04)
R.SL-V179

us(7)

3382
सचिव/सामान्य प्रशासन विभाग
दि. 27/4/2019

2. Further, it is also clarified that as per Policy Guidelines dated 06.08.2014, TDS is not applicable in respect of Central Samman Pension.
3. This issues with the approval of Competent Authority.

Yours faithfully,


(Meenu Batra)

Deputy Secretary to the Government of India

Tel No.23438062

Copy forwarded for information and similar action to:-

1. Chief Controller of Accounts, Central Pension Accounting Office (CPAO), Bhikaji Cama Place, Trikot-II, Behind Hotel Hyatt. Regency, New Delhi-110 066.
2. Chief Controller of Accounts (Pension and Misc.), 2/10, Jamnagar House, New Delhi- 110 011.
3. The Accounts Officer, Office of the Controller General of Accounts, Ministry of Finance, Lok Nayak Bhawan, New Delhi- 110 003.
4. Chief Secretaries of all State Governments/UT Administrations.
5. CPPCs of all 23 authorized banks (list attached).
6. Private Secretary to JS(FFR).
7. All Officers and staff of Freedom Fighter Division, Ministry of Home Affairs, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110 001.
8. PDMC, FFR Division, MHA.
9. IT Cell, MHA, North Block – for uploading this letter on MHA's website in the Document in Public Domain of FFR Division.


(Meenu Batra)

Deputy Secretary to the Government of India

18/Policy(FFR)-MHA

F.No.45/08/2017-FF(P)

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
Freedom Fighters & Rehabilitation Division

2nd Floor, NDCC-II Building,
Jai Singh Road, New Delhi – 110 001,
Dated 3rd October, 2018

To

The Chief Controller of Accounts,
Ministry of Home Affairs,
North Block, New Delhi-110 001

Subject: Grant of Dearness Relief to Central Freedom Fighter Pensioners w.e.f. 01.07.2018 -regarding

Sir,

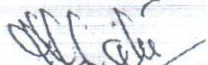
I am directed to refer to this Ministry's letter No.45/08/2017-FF(P) dated 12.04.2018(copy enclosed) regarding 5% Dearness Relief to be paid to the freedom fighter pensioners w.e.f. 01.01.2018 and to say that recently Dearness Relief in respect of Central Government pensioners has been enhanced by 2% by the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Pension & Pensioners' Welfare, New Delhi's O.M. No.42/06/2018-P&PW(G) dated 18.09.2018. Hence the Dearness Relief admissible to the Central Freedom Fighters/spouse/daughter pensioners shall be enhanced from the existing rate of 5% to 7% w.e.f. 01.07.2018. All the banks are requested to calculate the arrears w.e.f. 01.07.2018 and disburse in the month of October, 2018. The revised amount of pension for various categories of pensioners after increase of 2% DR i.e. total 7% Dearness Relief will be as follows:

Sl No.	Category of freedom fighters	Basic amount of pension (per month)	Enhanced amount of pension after adding 7% DR (per month) w.e.f. 01.07.2018
1.	Ex-Andaman Political prisoners/spouses	Rs.30,000/-	Rs.32,100/-
2.	Freedom fighters who suffered outside British India/spouses	Rs.28,000/-	Rs.29,960/-
3.	Other Freedom fighters/spouses including INA	Rs.26,000/-	Rs.27,820/-
4.	Dependent parents/eligible daughters (maximum 3 daughters at any point of time)	50% of the sum that would have been admissible to the freedom fighters, i.e. in the range of Rs.13,000/- to Rs.15,000/-	50% of the sum that would have been admissible to the freedom fighters, i.e. in the range of Rs.13,910/- to Rs.16,050/-

...p/2

2. Further, it is also clarified that as per Policy Guidelines dated 06.08.2014, TDS is not applicable in respect of Central Samman Pension.
3. This issues with the approval of Competent Authority.

Yours faithfully,


(Meenu Batra)

Deputy Secretary to the Government of India

Tel No.23438062

Copy forwarded for information and similar action to:-

1. Chief Controller of Accounts, Central Pension Accounting Office (CPAO), Bhikai Cama Place, Trikot-II, Behind Hotel Hyatt. Regency, New Delhi-110 066.
2. Chief Controller of Accounts (Pension and Misc.), 2/10, Jamnagar House, New Delhi- 110 011.
3. The Accounts Officer, Office of the Controller General of Accounts, Ministry of Finance, Lok Nayak Bhawan, New Delhi- 110 003.
4. Chief Secretaries of all State Governments/UT Administrations.
5. CPPCs of all 23 authorized banks (list attached).
6. Private Secretary to JS(FFR).
7. All Officers and staff of Freedom Fighter Division, Ministry of Home Affairs, NDCC-Building, Jai Singh Road, New Delhi-110 001.
8. PDMC, FFR Division, MHA.
9. IT Cell, MHA, North Block – for uploading this letter on MHA's website in the Document in Public Domain of FFR Division.


(Meenu Batra)

Deputy Secretary to the Government of India